दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

जून

2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- तंबाकू-मुक्त उत्तराखंड का संकल्प 3
- डॉ. नित्यानंद हिमालयन अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र का उद्घाटन 3
- उत्तराखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी 3
- विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते मुख्यमंत्री धामी 4
- नैनीताल में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कॉप स्थापित 4
- भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया 5
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर 5
- देवभूमि में एक एकड़ से कम भूमि में भी बनेंगे अमृत सरोवर 6
- फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड 6
- प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित 6
- जमरानी परियोजना के लिये केंद्र ने दी निवेश मंज़ूरी 7
- कैबिनेट बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण फैसले 7
- उत्तराखंड के 33 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने 8
- धामी ने ली विधानसभा सदस्य पद की शपथ 8
- 61 हज़ार बेटियों को मिलेगा ‘नंदा गौरा योजना’ का लाभ 9
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ‘नभ नेत्र’ का उद्घाटन 9
- देश भर की 75 हेरिटेज साइटों में हर की पौड़ी भी चयनित 10
- उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 10
- उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर लगेंगे 500 वाटर एटीएम 10
- उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक 11
- 15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्ग्रेस का शुभारंभ 11
- उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में तीन रोपवे परियोजनाओं को हरी झंडी 11
- सहस्त्रधारा 12
- बद्री-केदार की तर्ज़ पर विकसित होगा बागनाथ 12
- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बैठक 13
- राज्यपाल ने दिलाई नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को शपथ 13

नोट :

दृष्टि The Vision

उत्तराखंड

तंबाकू-मुक्त उत्तराखंड का संकल्प

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2022 को उत्तराखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 5 लाख से अधिक लोगों ने तंबाकू से परहेज़ करने का संकल्प लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज (जीडीएमसी) में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल (सेवानिवृत्त), डी.के. जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
- तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण के लिये तंबाकू-मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक तंबाकू की खपत को 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
- इस कार्यक्रम के तहत ही राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रखंड के दो गाँवों को तंबाकूमुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
- इस अवसर पर बोलते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि तंबाकू-मुक्त उत्तराखंड के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

डॉ. नित्यानंद हिमालयन अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2022 को दून विश्वविद्यालय की कुलपति (वीसी) सुरेखा डंगवाल ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जून को दून विश्वविद्यालय में डॉ. नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के भवन का उद्घाटन करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रसिद्ध हिमालयी भूगोलवेत्ता नित्यानंद के नाम पर केंद्र का निर्माण 22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- केंद्र की परिकल्पना हिमालयी क्षेत्र के सतत् विकास में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के लिये की गई है और इसका उद्देश्य क्षेत्र के सतत् विकास के लिये साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और शिक्षण के लिये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करना है।
- इसके अतिरिक्त 2 जून को ही मुख्यमंत्री केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय व्यावसायिक उन्नति कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में उत्तराखंड की महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं के कौशल और क्षमता को बढ़ाना है।

उत्तराखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी

चर्चा में क्यों?

2 जून, 2022 को देहरादून का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के घाटी वाले क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- देहरादून का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुँचने से पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि जून 2012 के अधिकतम 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद यह पहला अवसर है, जब तापमान 41 डिग्री तक पहुँच गया है।
- दून का अभी तक का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 43.9 डिग्री सेल्सियस है, जो 4 जून, 1902 को दर्ज़ किया गया था।
- गौरतलब है कि ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और यह मुख्यत: देश के उत्तर-पश्चिमी भागों को प्रभावित करती है।
- भारत में ग्रीष्म लहर सामान्यत: मार्च-जून के बीच चलती है, परंतु कभी-कभी जुलाई तक भी चला करती है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को ग्रीष्म लहर के मानक के रूप में निर्धारित किया है। जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर सामान्य तथा 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर गंभीर ग्रीष्म लहर की घटनाएँ होती हैं।

विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते मुख्यमंत्री धामी

चर्चा में क्यों ?

3 जून, 2022 को उत्तराखंड की चंपावत सीट के उपचुनाव संबंधी नतीजों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 92% मतों के साथ विजय प्राप्त की।

प्रमुख बिंदु

- चंपावत विधानसभा सीट के लिये 31 मई को हुए उपचुनाव में कुल 62,898 वोट पड़े थे।
- इसमें से 58,258 वोट मुख्यमंत्री धामी को, जबकि 3233 वोट कॉन्ग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को प्राप्त हुए।
- गौरतलब है कि धामी की यह जीत उत्तराखंड विधानसभा के चुनावों एवं उपचुनावों में मत प्रतिशत एवं मतों के अंतर के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 47 सीटें जीती थीं, किंतु मुख्यमंत्री धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट से हार गए थे।

नैनीताल में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कॉप स्थापित

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के निदेशक प्रो. दीपांकर बनर्जी ने बताया कि देवस्थल में स्थापित चार मीटर व्यास वाले लिक्विड मिरर टेलीस्कॉप की सहायता से एरीज अंतरिक्ष के बड़े रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- यह भारत के अतिरिक्त चार अन्य देशों- बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड एवं उज़्बेकिस्तान की साझा परियोजना है।
- वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से इस दूरबीन को निर्मित किया गया है।
- इसके पहले चरण के परीक्षण में 95 हज़ार प्रकाश वर्ष दूर NGC–4274 आकाशगंगा के स्पष्ट चित्र प्राप्त किये गए हैं, साथ ही अपनी आकाशगंगा मिल्की-वे के तारों की भी स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त की गई हैं।

भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित देवस्थल वेधशाला परिसर में भारत ने अपना पहला 'लिक्विड मिरर टेलीस्कोप' इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (ILMT) शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (ILMT) है, जिसे समुद्र तल से 2,450 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित किया गया है।
- इस टेलीस्कोप को नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES) के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है।
- खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिये विकसित किया गया यह दुनिया का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप है। यह दुनिया में कहीं भी चालू होने वाला अपनी तरह का अकेला टेलीस्कोप है।
- इस टेलीस्कोप का उपयोग दुनिया के किनारे पर मौजूद आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय तत्त्वों का निरीक्षण करने के लिये किया जाएगा।
- इस टेलीस्कोप को बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के सहयोग से भारत द्वारा स्थापित किया गया है। इसे बेल्जियम में एडवांस्ड मेकैनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज में डिजाइन किया गया और बनाया गया था।
- पारंपरिक दूरबीनों में एकल या घुमावदार सतहों के संयोजन के साथ पॉलिश किये गए काँच के दर्पण होते हैं और विशिष्ट रातों में विशेष खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिये उपयोग किये जाते हैं, जबकि तरल दर्पण दूरबीन (लिक्विड मिरर टेलीस्कोप) परावर्तक तरल पदार्थों, जैसे- मरकरी से बनी होती हैं और सितारों, आकाशगंगाओं, सुपरनोवा विस्फोटों, क्षुद्रग्रहों से लेकर अंतरिक्ष मलबे तक सभी संभावित खगोलीय पिंडों को कैप्चर करते हुए आकाश की एक पट्टी का अवलोकन करता है।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया, जिसमें उत्तराखंड को 7वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- मंडाविया ने एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स और ग्रांट्स फेज-II, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फेज-III, स्कूल स्तर पर एक प्रतियोगिता सहित विभिन्न नवीन पहलों की शुरुआत की।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि गुजरात 77.5 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
- बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड 55 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है।
- छोटे राज्यों में गोवा ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी, जबकि मणिपुर और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने शीर्ष तीन रैंक हासिल की।
- गौरतलब है कि राज्यों को खाद्य सुरक्षा के पाँच मानकों- मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व उपभोक्ता सशक्तीकरण पर आँका गया है।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था। नागरिकों के लिये सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेरित करने के लिये भी यह कदम उठाया गया था।

नोट :

देवभूमि में एक एकड़ से कम भूमि में भी बनेंगे अमृत सरोवर

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को मिशन अमृत सरोवर के राज्य समन्वयक मोहम्मद असलम ने बताया कि केंद्र सरकार ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत उत्तराखंड में सरोवर निर्माण के लिए निर्धारित क्षेत्रफल के मानक में छूट दे दी। अब उत्तराखंड में एक एकड़ से कम भूमि में भी सरोवर बन सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र ने यह छूट दी है।
- सरोवरों के नवनिर्माण एवं पुनर्जीवीकरण में 132.91 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिये जल संरक्षण की दृष्टि से इस वर्ष 24 अप्रैल को मिशन अमृत सरोवर की घोषणा की थी।
- स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के साथ इसे जोड़ते हुए प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वर्ष 15 अगस्त से पूर्व इन जलाशयों का निर्माण होना है।
- तय मानक के अनुसार एक सरोवर (जलाशय) का क्षेत्रफल एक एकड़ या इससे अधिक होना चाहिये।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तो जलाशय निर्माण के लिये एक एकड़ या इससे अधिक भूमि की उपलब्धता है, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस पर राज्य सरकार ने क्षेत्रफल के मानक में छूट देने का आग्रह किया, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया।
- मिशन के राज्य समन्वयक मोहम्मद असलम ने बताया कि सभी 13 ज़िलों के लिये निर्धारित 975 सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 1017 सरोवर चयनित किये गए हैं। अब तक 530 सरोवर स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 333 पर कार्य प्रारंभ हो गया है।
- अन्य सरोवरों के निर्माण एवं पुनर्जीवीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। अधिकांश सरोवर मनरेगा के अंतर्गत बनाए जाएंगे।

फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2022 को उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विश्व खाद्य योजना के तहत उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही राज्य में फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य होगा। वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम योजना सिर्फ ओडिशा और हरियाणा राज्य में चल रही है।
- मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकारी राशन की दुकान से मिलने वाले मुफ्त राशन के लिये पात्र लोगों को अब दुकानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिस तरह आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी ज़रूरत के लिये पैसे निकालते हैं, अब उसी तरह पात्र लोग अनाज ले सकते हैं।
- यह सिस्टम एटीएम मशीन की तरह काम करेगा। साथ ही इस पर एटीएम मशीन की तरह स्क्रीन होगी। राशनकार्ड धारक यहाँ आकर एटीएम मशीन की तरह गेहूँ, चावल व दाल निकाल सकेंगे। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है।

प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों ?

9 जून, 2022 को उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशालय के निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के तहत सभी निकायों को 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित करने से संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 4 जून को शहरी विकास निदेशालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित की जाए।
- इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रॉन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।
- ललित मोहन रयाल ने बताया कि निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिये हैं। निदेशालय प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।
- प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिकयुक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी।
- इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।
- गौरतलब है कि प्रदेश भर में पहले भी 50 माइक्रॉन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

जमरानी परियोजना के लिये केंद्र ने दी निवेश मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

10 जून, 2022 को नई दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में निवेश मंज़ूरी प्रस्तावों पर हुई बैठक में उत्तराखंड की महत्त्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को निवेश मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मणिपुर की परियोजनाओं के लिये निवेश मंज़ूरी के प्रस्तावों पर विचार किया गया।
- बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को मंज़ूरी दी गई। मंज़ूरी 90:10 (केंद्र: राज्य) के आधार पर दी गई है।
- इस परियोजना का लक्ष्य 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करना है और इससे 57,065 हेक्टेयर भूमि के लिये अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- यह परियोजना वर्ष 2055 तक हल्द्वानी शहर को 42 एमसीएम पेयजल भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले में गोला नदी पर बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के प्रथम चरण में गोला बैराज का निर्माण, 244 किमी. नहर का पुनर्निर्माण और दामुवा एवं अमृतपुरी कॉलोनी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण फैसले

चर्चा में क्यों?

10 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर विचार किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद ने सितारगंज चीनी मिल को भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से आउटसोर्स कर संचालित किये जाने की स्वीकृति दी।

नोट :

- मंत्रिपरिषद ने राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति प्रदान की।
- इसके अलावा वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई, जो निम्नलिखित हैं-
  - परमवीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये एकमुश्त अनुदान 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए।
  - अशोक चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए।
  - महावीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए।
  - कीर्ति चक्र विजेताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए।
  - वीर चक्र और शौर्य चक्र के लिये 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए।
  - सेना वीरता पदक के लिये 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए।
  - डिस्पैच में मेंशन के लिये 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए।
- मंत्रिपरिषद ने सिंचाई विभाग की साथी सेवा नियमावली को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम संशोधन विधेयक, 2022 और उत्तराखंड अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक, 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में संशोधन के संबंध में संबंधित विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्देश दिया कि एकल आवासीय-व्यावसायिक भवनों से नर्सिंग होम, क्लीनिक, चाइल्ड केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल आदि के कंपाउंडिंग के लिये एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

उत्तराखंड के 33 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने

चर्चा में क्यों ?

11 जून, 2022 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंगआउट परेड (पीओपी) के बाद उत्तराखंड के 33 युवा भारतीय सेना में अधिकारी बन गए।

प्रमुख बिंदु

- परेड में देश-विदेश के कुल 377 कैडेट्स ने शिरकत की। 150 रेगुलर कोर्स और 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (टीजीसी) से संबंधित कुल 288 जेंटलमैन कैडेट्स (जीसी) 11 जून को पासिंगआउट के बाद भारतीय सेना के गर्वित अधिकारी बन गए।
- आठ मित्र देशों के 89 जेंटलमैन कैडेट्स भी पासआउट होकर अपने-अपने देश की सेनाओं में शामिल हो गए हैं। मित्र देशों में अफगानिस्तान से 43, भूटान से 18, किर्गिस्तान से 1, मालदीव से 3, नेपाल से 1, श्रीलंका से 3, ताजिकिस्तान से 19, तंजानिया से 1 कैडेट पास आउट हुए।
- उत्तर प्रदेश 50 अधिकारियों के साथ जीसी के राज्यवार प्रतिनिधित्व की तालिका में सबसे आगे रहा। पासिंगआउट दल में 33 जीसी के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, जबकि बिहार 28 जीसी के साथ तीसरे स्थान पर तथा हरियाणा 25 जीसी के साथ चौथे स्थान पर रहा।
- कोर्स के हरफनमौला जेंटलमैन कैडेट बिहार के समस्तीपुर निवासी मौसम वत्स को प्रतिष्ठित सोर्ड ऑफ ऑनर और ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर निवासी नीरज सिंह पपोला को गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
- गौरतलब है कि भारतीय सैन्य अकादमी से अब तक कुल 34 मित्र देशों के 2724 कैडेट्स पासआउट हो चुके हैं, जबकि भारतीय सैनिक अकादमी अब तक 63 हज़ार 568 सैन्य अधिकारी देश को दे चुकी है।

धामी ने ली विधानसभा सदस्य पद की शपथ

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा भवन में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 3 जून, 2022 को चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड मत प्रतिशत से जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री धामी तीसरी बार विधायक बने हैं।
- गौरतलब है कि मार्च में हुए विधानसभा चुनाव, 2022 में भाजपा ने 60 में से 47 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, परंतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट से कॉन्ग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी से हार गए थे।
- खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री धामी के लिये चंपावत से विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी ने इस्तीफा देकर सीट खाली की थी।

61 हज़ार बेटियों को मिलेगा 'नंदा गौरा योजना' का लाभ

चर्चा में क्यों?

15 जून, 2022 को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने 'नंदा गौरा योजना' का लाभ देने के लिये बजट में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

प्रमुख बिंदु

- इससे वर्ष 2022-23 के लिये राज्य के गरीब परिवारों की 61 हज़ार से अधिक बेटियों को 'नंदा गौरा योजना' का लाभ मिल सकेगा। योजना के माध्यम से सामान्य श्रेणी से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाली बेटियों के जन्म पर 11 हज़ार और इंटर पास करने पर 51 हज़ार की धनराशि दी जाती है, ताकि बेटियाँ इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।
- इस कल्याणकारी योजना में बजट की कमी के चलते वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक गरीब परिवारों की 61,890 बेटियों को 'नंदा गौरा योजना' का लाभ नहीं मिल पाया। विभाग की ओर से वर्ष 2019-20 में 1421 बेटियों को, वर्ष 2020-21 में 16,336 एवं वर्ष 2021-22 में 44,133 बेटियों को योजना का लाभ नहीं मिला।
- विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 में 27,239 वर्ष 2020-21 में मात्र 31,043 बेटियों को योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि वर्ष 2021-22 में एक भी पात्र बेटी को योजना का लाभ नहीं मिला।
- विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बेटियों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिये सरकार से 375 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन इसके विपरीत मात्र 60 करोड़ रुपए मिले।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 'नभ नेत्र' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन 'नभ नेत्र' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है तथा किसी भी आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित यह मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा।
- आईटीडीए निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आने या आपात् स्थिति बनने के समय डाटा जुटाने, प्रोसेस करने और स्थिति पर निगरानी रखने जैसी चुनौतियाँ रहती हैं। अब इन तमाम मोर्चों के लिये ड्रोन तकनीक की मदद बड़े पैमाने पर ली जा सकेगी। इसके लिये ड्रोन एप्लिकेशन रिसर्च सेंटर ने मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन विकसित किया है, जिसका उपयोग आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान ड्रोन का उपयोग करने एवं ड्रोन के माध्यम से डाटा एकत्रित करने में किया जाएगा।
- इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात् मानचित्र तैयार किया जाएगा।

- यह स्टेशन पूरी तरह एक वाहन पर स्थापित किया गया है। इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को डाटा प्रोसेसिंग के लिये हाई स्पीड वर्कस्टेशन, बैंडविड्थ एग्रीगेशन और बिना नेटवर्क ज़ोन वाले क्षेत्रों के लिये वीसैट से युक्त किया गया है।
- इस वाहन का उपयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन और सभी संवेदनशील आपदा संभावित क्षेत्रों की 3डी मैपिंग के लिये किया जाएगा।

देश भर की 75 हेरिटेज साइटों में हर की पौड़ी भी चयनित

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2022 को हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि 75वें स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में चयनित 75 हेरिटेज साइटों में उत्तराखंड राज्य के हर की पौड़ी का भी चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत राज्य के हर की पौड़ी के मालवीय घाट पर योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हरिद्वार के पाँच स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा ममता आनंद, आचार्य बिपिन जोशी, सीमा जौहर, संजीव चांदना, स्वरूपसिंह भंडारी, शशिकांत दूबे, मनोज जायसवाल, त्रिलोक सैनी समेत 17 योग शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया।

उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंज़ूरी भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक महीने के भीतर ही प्रदान कर दी गई है।
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।
- उत्तराखंड हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या 9 तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 2 है।

उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर लगेंगे 500 वाटर एटीएम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड पेयजल विभाग के सचिव नितेश झा ने बताया कि प्रदेश में पानी की प्लास्टिक बोतलों का प्रचलन कम करने, ग्रामीणों को स्वरोज़गार और पर्यटकों को स्वच्छ पानी देने के लिये हर पर्यटन स्थल पर अत्याधुनिक वाटर एटीएम लगेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विभाग की ओर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहले चरण में लगने वाले 500 अत्याधुनिक वाटर एटीएम के संचालन की ज़िम्मेदारी संबंधित पर्यटन स्थल की ग्राम पंचायत को दी जाएगी।
- सभी वाटर एटीएम पर उस पानी की गुणवत्ता डिस्प्ले की जाएगी। पर्यटकों को यह पता रहेगा कि वे किस स्तर का पानी पी रहे हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट कम करने के लिये राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई, 2022 से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा।

उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन उत्कृष्टता केंद्र और वन्यजीव स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- टाइगर रिज़र्व, संरक्षित क्षेत्र व अन्य पर्यटन वन क्षेत्रों में पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाइडलाइन बनाई जाएंगी।
- राज्य सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ ही वनाग्नि रोकने के लिये गाँव स्तर पर प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम (पीआरटी) बनाई जाएंगी।

15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्ग्रेस का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा में आयोजित 15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्ग्रेस का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्ग्रेस और उत्तराखंड के बहुमूल्य उत्पादों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।
- गौरतलब है कि गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण साइंस कॉन्ग्रेस का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिये यूकास्ट (UCOST) द्वारा 15वीं एवं 16वीं साइंस कॉन्ग्रेस का साझा आयोजन किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद वैज्ञानिक एवं शोधार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से संकल्प को शक्ति बनाकर 'विकल्प रहित संकल्प' के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ें।
- उन्होंने कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिये 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' के क्षेत्र से जुड़े सभी वैज्ञानिक एवं शोधार्थियों के सुझाव आमंत्रित हैं।

उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में तीन रोपवे परियोजनाओं को हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडीदेवी रोपवे परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बैठक में इन तीन महत्त्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को मंज़ूरी के साथ ही नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजने का अनुमोदन किया गया।
- इसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किमी. रोपवे परियोजना के तहत 26.43 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है, जबकि गोविंदघाट से हेमकुंड तक करीब 12.5 किमी. रोपवे परियोजना के लिये 27.4782 हेक्टेयर वन भूमि और हरिद्वार में हरकी पैड़ी से चंडीदेवी तक रोपवे परियोजना के लिये 0.29 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है।
- बैठक में उत्तरकाशी ज़िले में संरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने वाले रॉकी नॉव से मुलिग्ला तक ऑपरेशनल ट्रैक निर्माण और सुगमा वाई जंक्शन से थांगला-दो तक ऑपरेशनल ट्रैक निर्माण के लिये भी क्रमश: 7.20 हेक्टेयर और 3.4214 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को मंज़ूरी दी गई।
- बैठक में अल्मोड़ा ज़िले के तहत बनने वाले चार मोटर मार्गों के लिये भी भूमि हस्तांरण का अनुमोदन किया गया। हरिद्वार में बनने वाली रिंग रोड के लिये 48.895 हेक्टेयर और जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना के लिये 400.89 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी अनुमोदन के बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा।
- वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत, हाइड्रो, उप-खनिज चुगान, औद्योगिक विकास के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।।
- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन उत्कृष्टता केंद्र और वन्यजीव स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की प्रदेश में स्थापना की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राइमरी रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया जाएगा, जो वन व वन्यजीव संरक्षण के साथ ही वनाग्नि को रोकने पर भी काम करेंगी।
- टाइगर रिज़र्व, संरक्षित क्षेत्र व अन्य पर्यटन वन क्षेत्रों में पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाईडलाइन बनाई जाएगी, ताकि स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सके।

सहस्त्रधारा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल 'सहस्त्रधारा' को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिये हज़ारों पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने इस शर्त पर प्रस्ताव को मंज़ूरी दी कि राज्य द्वारा इन मूल्यवान पेड़ों को फिर से लगाया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी।
- सहस्त्रधारा, जिसका शाब्दिक अर्थ 'Thousand Fold Spring' है, बाल्दी नदी पर देहरादून से 16 किमी. की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
- सहस्त्रधारा प्राकृतिक सल्फर वाटर स्प्रिंग है, जिसमें विविध प्रकार के औषधीय गुण हैं, जैसे- इसके जल के उपयोग से त्वचा रोगों का तथा उदरीय विकारों का उपचार संभव है।
- सहस्त्रधारा का जल चूने के अवशेषों से एक प्रक्षेपित पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। यहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर में स्थित गुफा को द्रोण गुफा के रूप में जाना जाता है, जिसमें चट्टान से उकेरे गए कई लघु शिवलिंग हैं।

बद्री-केदार की तर्ज़ पर विकसित होगा बागनाथ

चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2022 को उत्तराखंड पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का विकास बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज़ पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत मंदिर परिसर की सभी दुकानों को पारंपरिक पर्वतीय शैली में एक समान तरीके से विकसित किया जाएगा।
- सरयू नदी के तट पर घाटों का निर्माण होगा, जबकि मंदिर परिसर में लाइट एंड साउंड शो और संग्रहालय के निर्माण की भी सुविधा होगी।
- मंदिर के चारों ओर एक अग्रभित्ति और भित्ति चित्रों का उपयोग मंदिर को एक नया रूप देने के लिये किया जाएगा।
- चंडिका मंदिर से नीलेश्वर मंदिर तक रोपवे का निर्माण, पुलों का सौंदर्यीकरण व प्रसाद के लिये स्मारिका दुकान की भी सुविधा होगी।
- गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थस्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था, जिसका नाम बदलकर अक्टूबर 2017 में 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (यानी 'प्रसाद') राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

27 जून, 2022 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बोर्ड की 22वीं बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनका विवरण निम्नलिखित है-
  - सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण 1200 करोड़ रुपए और हेमकुंड साहिब से गोविंदघाट रोपवे का निर्माण 850 करोड़ रुपए से किया जाएगा।
  - औली को साहसिक गतिविधियों के लिये ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिये 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
  - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये परिषद की गतिविधियों को संचालित करने हेतु कुल 55 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया।
  - पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, एडवेंचर समिट, स्कीइंग चैंपियनशिप, टिहरी झील महोत्सव, योग महोत्सव के आयोजन का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया।
- इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिये गए हैं-
  - हुनर से रोज़गार योजना के तहत कुकिंग, सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के लिये 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - कैरावान टूरिज़्म, चाय बगान टूरिज़्म, होम स्टे टूरिज़्म, नेचर गाइड में भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।
  - ऋषिकेश में गंगा क्याक फेस्टिवल, टिहरी में कैनोइंग फेस्टिवल, बौर जलाशय में क्याकिंग चैंपियनशिप, योग महोत्सव, छोटा कैलाश माउंटेनियरिंग अभियान, पिंडारी में ट्रैक ऑफ-द इयर के साथ हाई एंड लो एल्टीट्यूड ट्रैकिग ट्रेनिंग के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

राज्यपाल ने दिलाई नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को शपथ

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने देश के राष्ट्रपति की ओर से न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना पढ़ी।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने 17 मई, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। विपिन सांघी ने नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
- न्यायमूर्ति विपिन सांघी का जन्म 27 अक्टूबर, 1961 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सन् 1980 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा सन् 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी गणित (ऑनर्स) से स्नातक किया और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की। इसी वर्ष उन्होंने एक वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया।
- सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के पैनल वकील के रूप में भी सांघी नियुक्त हुए। वहीं दिसंबर 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलनों में भाग लिया है।
- न्यायमूर्ति विपिन सांघी 29 मई, 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तथा 11 फरवरी, 2008 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 13 मार्च, 2022 से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

दृष्टि The Vision

नोट :